शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य के शिक्षा मंत्री को सलाह दी गई थी कि नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की बजाय दरभंगा के वर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय को प्रस्तावित मिथिला विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया जाए। इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अब एक पत्र प्राप्त हुआ है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों की वित्तीय स्थिति

1006. श्री विभूति मिश्र
श्री क० ना० तिवारी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कुछ कालेजों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा शिक्षा मंत्रालय का विचार कालेजों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । किन्तु दिल्ली के कालेजों को और अधिक उदारतापूर्वक अनुरक्षण अनुदान देने तथा कुछ मामलों में प्रबन्ध मण्डलों को उस अवधि तक अपने हाथ में लेने के प्रश्न की जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित एक समिति द्वारा हाल ही में जांच की गई है। इसकी सिफारिशें इस समय आयोग के विचाराधीन हैं।

Central Assistance to Professional Colleges in J & K

1007. **Shri Abdul Ghani Dar:** Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the amount of Central assistance given to medical, Engineering and Agricultural colleges in Jammu and Kashmir during the last three years;

(b) the number of Medical, Engineering and Agricultural Colleges separately in Jammu and Kashmir at present; and

(c) the percentage of minorities to whom admission is given in these colleges?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (c). The required information is being collected and *will be placed on the Table of the* House.

Local Telephone Call Rates in Delhi

1008. **Shri V. Krishnamoorthy:**
Shri S. Supakar:
Shri N. R. Laskar:
Shri D. C. Sharma:
Shri Yashpal Singh:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Y. A. Prasad:
Shri N. K. Sanghi:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government have revised local-telephone call rates in respect of the Public Call Telephone Booths in Delhi;

(b) if so, the reasons for the upward revision of the rates; and

(c) the anticipated increase in the revenue on this account?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes Sir, the rates have been revised throughout the country including Delhi.

(b) It is not possible to change the mechanism of the coin box type public call offices to operate with the proposed coin of 5 paise denomination of considerably lesser weight. The mechanism has, therefore, to be made operative with two coins of 10 paise denomination.

(c) The anticipated additional revenue for the whole of the country is expected to be of the order of Rupees 4 lakhs per annum.

काश्मीर में जनमत संग्रह

1009. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कि काश्मीर आवामी संघर्ष समिति ने श्रीनगर में 1 अप्रैल, 1967 की इस मांग को पुनः दुहराया है कि काश्मीर में जनमत संग्रह कराने की व्यवस्था की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1967 को काश्मीर अवामी संघर्ष समिति ने तो ऐसी कोई मांग नहीं की थी किन्तु सरकार को समिति का काश्मीर के लिए आत्म निर्णय सम्बन्धी दृष्टिकोण ज्ञात है । इस बारे में अनेक अवसरों पर सरकार ने अपने दृष्टिकोण की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है और उसको देखते हुए काश्मीर में जनमत संग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में शहरी सम्पत्ति कर

1010. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च-स्तरीय आयोग ने सिफारिश की है कि राजधानी में समस्त शहरी सम्पत्ति पर भूमि-कर लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सिफारिश को क्रियान्वित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). स्थानीय निकायों की वित्त व्यवस्थाओं की जांच करने के लिये नियुक्त जांच-आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि लाभ के लिये प्रयोग में आने वाली या आ सकने योग्य समस्त शहरी सम्पत्ति पर, जिसमें सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भी शामिल हैं, सम्पत्ति के मूल्य के 2½ प्रतिशत की दर से विकास कर लगाने के लिये एक उपयुक्त विधि-नियम स्वीकार किया जाय । तथापि आयोग ने बाद में 7-3-1967 को अपनी बैठक में अपनी सिफारिशों की पुनः परीक्षा करने का निश्चय किया । आयोग के अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

त्रिपुरा में भीषण आंधी

1011. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में त्रिपुरा में भीषण आंधी के फलस्वरूप जान व माल की भारी हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सहायता की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एल० राजास्वामी) : (क) और (ख). अप्रैल 1967 की 15, 17 और 18 तारीखों को त्रिपुरा के बहुत बड़े भाग में तूफानी आन्धियों और भीषण वर्षों का आक्रमण